



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 31]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2018/पौष 13, 1939

No. 31]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2018/PAUSHA 13, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2018

का.आ. 42(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 29 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना संख्या का. आ. 952 (अ) के तहत मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता को उक्त अधिनियम की धारा 11 के उप-खण्ड (1) के प्रयोजनार्थ विशेष न्यायालय के तौर पर अधिसूचित किया था जिसका क्षेत्राधिकार अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के लिए संपूर्ण पश्चिम बंगाल राज्य था;

और जबकि, श्री कुंदन कुमार कुमई, मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 09 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1864 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानांतरण हो गया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 09 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1864 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, कलकत्ता उच्च न्यायालय के माननीय पदेन मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर एतद् द्वारा श्री प्रसेनजीत बिस्वास, मुख्य न्यायाधीश, सिटी सत्र न्यायालय, कलकत्ता को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009-आईएस-IV-(भाग-V)]

सुधीर कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd January, 2018

S.O. 42(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 952 (E) dated the 29th April, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of West Bengal for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri Kundan Kumar Kumai, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 1864 (E) dated the 9th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 1864 (E), dated the 9th June, 2017, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Acting Chief Justice, High Court, Calcutta, hereby appoints Shri Prasenjit Biswas, Chief Judge, City Sessions Court, Calcutta, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-V)]

SUDHIR KUMAR SAXENA, Jt. Secy.